न्यायमूर्ति वी. के. बाली और बी. राय के समक्ष .

एम. एम. शर्मा,-अपीलार्थी

बनाम

दिलावर सिंह-प्रतिवादी

C.A.C.P. सं. 20 of 1998

20 जनवरी, 1999

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 – धारा 10 और 19.1-उच्च न्यायालय के नियम और आदेश, खंड 4- नियम 9 और 10 का अध्याय 12 भाग बी- अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रेवाड़ी को जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा पारित स्थगन आदेश का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया गया- दोषसिद्धि के खिलाफ अपील -वादी के खिलाफ पारित सेवा से निलंबन का आदेश निचली अदालत द्वारा रोक दिया गया और अपील में एडीजे ने उस दिन निचली अदालत के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी जब वादी द्वारा एडीजे के बोर्ड से मामले को स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरण आवेदन भी लंबित और सुना गया था- जिला न्यायाधीश ने एडीजे के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी-स्थगन आदेश पारित करने की जानकारी का तथ्य स्थापित नहीं हुआ और न ही इसलिए, उसकी अवज्ञा-वादी का आवेदन और शपथ पत्र जिसमें शपथ आयुक्त के समक्ष शुरू नहीं की गई अंतर्विरोध शामिल थे, जिसके समर्थन में मध्यस्थता वादी ने यह दिखाने की मांग की थी कि एडीजे को स्थगन की जानकारी थी

अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी को उच्चतर न्यायालय अर्थात जिला न्यायाधीश, नारनौल के न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के बारे में जानकारी नहीं थी और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है की प्रत्यर्थी द्वारा बाद में "और कार्यवाहियों के स्थगन" शब्दों को जोड़ने की संभावना थी, अर्थात जब अपीलार्थी पहले ही अंतरिम आदेश कर चुका था। इन परिस्थितियों में हमारी राय है कि अपीलार्थी को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी नहीं थी और उसने जानबूझकर उसकी अवज्ञा नहीं की थी।किसी भी मामले में, यह बहुत संदिग्ध है कि उन्हें ऐसा ज्ञान था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को किसी विशेष मामले की सुनवाई में रुचि नहीं होनी चाहिए, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी देखा गया है लेकिन यह भी उतना ही सच है कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को किसी भी मामले की सुनवाई और निर्णय लेने से डरना नहीं चाहिए।

(पैरा 24)

आर. एस. चीमा,वरिष्ठ अधिवक्ता सहित आर. एस. सिहोटा , अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

विजय जिंदल अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय

न्यायमूर्ति वी. के. बाली.

(1) यह अपील इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2 दिसंबर, 1998 को पारित एक आदेश से उत्पन्न होती है, जिसमें अपीलकर्ता-एम. एम. शर्मा, हरियाणा राज्य में रेवाड़ी में तैनात एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, को अवमानना का दोषी ठहराया गया है, जिसने उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है और उनपे 1, 000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

(2) कानून और तथ्य दोनों के मुद्दों पर, अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री चीमा, ने विद्वान एकल न्यायाधीश श्री विजय जिंदल द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया हैं। प्रत्यर्थी-दिलावर सिंह के विद्वान वकील, कानून या तथ्य के सभी प्रश्नों पर श्री चीमा के साथ मुद्दों में शामिल होते हैं और स्पष्ट रूप से इस अपील को खारिज करने का अनुरोध करते हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई दलीलों पर विचार करने और उन पर टिप्पणी करने से पहले, प्रत्यर्थी द्वारा अवमानना याचिका दायर करने की घटनाओं की पृष्ठभूमि देना उपयोगी होगा, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, भले ही विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तथ्यों को विस्तार से दिया गया हो।

(3) दिलावर सिंह, जिन्हें सुनवाई के दौरान हमें सूचित किया गया था और जैसा कि 14 दिसंबर, 1998 के हमारे अंतरिम आदेश में दर्ज है और 4 सितंबर, 1998 के उनके जवाबी हलफनामे में भी दर्ज है, एक समय में वकील थे और बार एसोसिएशन, पानीपत के उपाध्यक्ष भी रहे।हालांकि, प्रासंगिक समय में, वह हरियाणा राज्य में सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारी के पद पर थे।अनुशासनहीनता के कुछ कृत्यों के लिए 31 दिसंबर, 1997 को निलंबित कर दिया गया था।उन्होंने 6 जनवरी, 1998 को दायर किए गए दीवानी मुकदमे के माध्यम से उपरोक्त आदेश को चुनौती दी।मुकदमे की सुनवाई के दौरान, उन्होंने प्रतिवादी-राज्य को निर्देश देते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन पेश किया ताकि निलंबन के आदेश को लागू न किया जा सके। दीवानी अदालत, जिसके समक्ष स्थगन देने के संबंध में मामला सुनवाई के लिए आया, ने राज्य को निलंबन के विवादित आदेश को लागू करने से रोक दिया।उक्त आदेश, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित निर्णय से स्पष्ट है, राज्य को सुने बिना पारित किया गया

था।इस एकपक्षीय आदेश के खिलाफ, विभाग ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रेवाड़ी के न्यायालय में एक अपील की, जो अपीलार्थी के समक्ष सुनवाई के लिए आई। 9 फरवरी, 1998 के आदेश के माध्यम से, अपीलार्थी ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया और निषेधाज्ञा के एकपक्षीय आदेश को रद्द कर दिया। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय में एक सिविल पुनरीक्षण दायर किया, जिसका निपटान 16 मार्च, 1998 को किया गया था, जिसमें निचली अदालत को 9 फरवरी, 1998 के अपने आदेश से प्रभावित हुए बिना, आदेश प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर स्थगन के लिए आवेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था ।निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने के संबंध में मुकदमे की इस दूसरी लड़ाई में, विद्वत निचली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक बार फिर 16 मई, 1998 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी को निषेधाज्ञा प्रदान की।विवश होकर, राज्य ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रेवाड़ी के न्यायालय में एक अपील दायर की, जो एक बार फिर अपीलार्थी के समक्ष सुनवाई के लिए आई।दिलावर सिंह, जो स्वाभाविक रूप से उक्त अपील में प्रतिवादी थे, ने अपने वकील श्री एन. एस. सचदेवा, अधिवक्ता के माध्यम से कैविएट दायर किया था। प्रत्यर्थी का मामला है कि उसने अपीलार्थी के समक्ष लंबित अपील को किसी अन्य सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अपने वकील के माध्यम से एक आवेदन भी मुख्य रूप से इस आधार पर दायर किया था कि अपीलार्थी ने पहले ही 9 फरवरी, 1998 को राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए अपना विचार व्यक्त कर दिया था, जिसके खिलाफ उसने इस न्यायालय में एक संशोधन को प्राथमिकता दी थी, जिसके परिणाम का पहले ही उल्लेख किया गया था।यह उनका मामला रहा है कि उपरोक्त स्थानांतरण आवेदन 27 मई, 1998 को जिला न्यायाधीश, नारनौल के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिन्होंने बदले में हरियाणा राज्य को 4 जून, 1998 के लिए नोटिस जारी किया और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, यानी अपीलार्थी के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। प्रतिवादी का मामला आगे यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थी को न केवल जिला न्यायाधीश, नारनौल के समक्ष स्थानांतरण आवेदन के लंबित होने और उसमें निर्धारित तिथि के बारे में सूचित किया गया था, बल्कि यह भी कि अपीलार्थी के समक्ष लंबित उक्त अपील में आगे की कार्यवाही पर तब से रोक लगा दी गई है, अपीलार्थी ने फिर भी मामले को आगे बढ़ाया और राज्य पर रोक लगा दी, यह जिला न्यायाधीश, नारनौल का आदेश है जिसका अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा लगाए गए आरोप का कारण, इस प्रकार, जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा पारित 27 मई, 1998 के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन है।

(4) एकल न्यायाधीश द्वारा नोटिस करे जाने पर अपीलार्थी ने बचाव पेश किया और व्यावहारिक रूप से सभी तथ्यों को स्वीकार किया, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हालाँकि विद्वान जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा 27 मई, 1998 को दिए गए स्थगन की जानकारी का खंडन किया।इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश या हमारे समक्ष निर्धारण के

लिए जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया गया, वह यह था कि क्या अपीलार्थी को लिखित रूप में सूचित किया गया था, जैसा कि प्रत्यर्थी का मामला है, कि जिला न्यायाधीश, नारनौल ने 27 मई, 1998 के अपने आदेश के माध्यम से राज्य द्वारा दायर एक अपील में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जो स्वीकार्य रूप से लंबित थी और उसी तारीख, यानी 27 मई, 1998 को अपीलार्थी के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी।हालाँकि, इससे पहले कि हम ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक मुद्दे पर पक्षों के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर ध्यान दें, यह कहना उचित होगा कि चाहे वह आपराधिक हो या दीवानी अवमानना, अवमानना का गठन करने वाले आरोपों को उसी तरह साबित करना होगा जैसे कि आपराधिक आरोप को साबित करना होता है। इसलिए, जब तक एक निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता कि एक पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होते हैं, अवमानना मामले में दोषसिद्धि का कोई आदेश दर्ज नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, जब किसी न्यायिक कार्यालय के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाता है, और उसके समक्ष लंबित न्यायिक कार्यवाही में उसके द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न होता है, तो यह देखना आगे प्रासंगिक हो जाता है कि क्या संबंधित न्यायिक अधिकारी का जानबूझकर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करने का कोई इरादा था।

(5) एस एस रॉय बनाम ओरिसा राज्य[1] में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, जिसने अपनी शक्तियों को गलत समझकर, कानून द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया और बिना किसी उचित परिस्थितियों के, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश किया जिसके माध्यम से एक सिविल कोर्ट के चपरासी को धन डिक्री के निष्पादन के संबंध में एक अतिरिक्त मुन्सिफ द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने से रोक दिया गया था, यह अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट आदेश देने में किसी भी बाहरी विचार या बेईमान उद्देश्य से प्रभावित नहीं था। आगे कहा गया कि "मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुन्सिफ की अदालत की अवमानना का दोषी नहीं पाया जा सकता क्योंकि उनकी ओर से जानबूझकर कार्य किए जाने का कुछ भी नहीं था।मामले के संक्षिप्त तथ्यों से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश देने के कारण अवमानना का दोषी पाया गया था, जिसके द्वारा एक दीवानी अदालत के चपरासी को एक धन डिक्री के निष्पादन के संबंध में एक अतिरिक्त मुन्सिफ द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने से रोक दिया गया था।उच्च न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश देने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्तियों को गलत समझा और उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं था और ऐसी कोई परिस्थिति मौजूद नहीं थी जो मजिस्ट्रेट को धारा 144 सीआरपी के तहत उस प्रकृति का आदेश पारित करने में उचित ठहराए। हालांकि, इस तरह से अभिनिर्धारित करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट आदेश देने में किसी

---

1 ए. आई. आर. 11960 पाउंड एस. सी. 1190

भी बाहरी विचार या बेईमान उद्देश्य से प्रभावित नहीं था। *बार्टन बनाम फील्ड*[2] में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि त्रुटि अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्यों से आगे बढ़ने वाली एक जानबूझकर त्रुटि होनी चाहिए ताकि उसे अदालत की अवमानना के लिए दंडित किया जा सके।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि तथ्यों के आधार पर, मजिस्ट्रेट के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने उचित देखभाल और सावधानी के बिना काम किया था, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी ओर से किसी भी जानबूझकर दोषी होने का सुझाव दे।भले ही, अंतिम विश्लेषण में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने किसी भी तरह से मजिस्ट्रेट के आचरण को मंजूरी नहीं दी, लेकिन उसके खिलाफ अवमानना में कार्यवाही के लिए कोई न्यायनिर्णयन नहीं था। *बी. के. कर बनाम माननीय मुख्य न्यायाधीश और अन्य*[3] में, यह कहा गया था कि "किसी अधीनस्थ अदालत को उच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने और इस प्रकार अदालत की अवमानना करने का दोषी पाए जाने से पहले, यह दिखाना आवश्यक है कि अवज्ञा जानबूझकर की गई थी।किसी आदेश की अवज्ञा करने के इरादे का अनुमान लगाने के लिए कोई जगह नहीं है जब तक कि आरोपित व्यक्ति को आदेश की जानकारी न हो।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि "ज्ञान एक ऐसे स्रोत से प्राप्त किया जाना चाहिए जो या तो अधिकृत है या अन्यथा प्रामाणिक है और इसे एक कानून के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक तार (उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में) जो एक अधिवक्ता या एक वकील द्वारा हस्ताक्षरित होने का तात्पर्य है, उसमें बताए गए तथ्यों की सच्चाई का और इस तथ्य का भी आश्वासन देता है कि यह वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा भेजा गया था जिसके नाम पर यह है।इन मामलों के बारे में अधीनस्थ अदालत को आश्वस्त करने के लिए पक्ष से एक हलफनामा आवश्यक होगा।"

(6) दूसरा प्रस्ताव अब अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का आरोप यह है कि अवमानना के आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति को आदेश की जानकारी थी, तो जो यह दावा करता है कि किसी व्यक्ति को आदेश की जानकारी थी, उसे इस तथ्य को हर युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा। यदि कोई संदेह है, तो अदालत की अवमानना के आरोपी व्यक्ति को लाभ दिया जाना चाहिए।यह ऐसा *भुन्न प्रसाद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*[4] में आयोजित किया गया था।

(7) उन सिद्धांतों का विश्लेषण करने के बाद जिन पर महत्वपूर्ण प्रश्न को निर्धारित करने की आवश्यकता है, अब अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के प्रामाणिक ज्ञान का सुझाव देने वाले साक्ष्य का आकलन करने का समय आ गया है।जबकि, यह प्रत्यर्थी का सकारात्मक मामला है कि उसने एक हलफनामे द्वारा समर्थित उस ओर से आवेदन करते समय लिखित रूप में अपीलार्थी को स्थगन के तथ्य को सूचित किया था,

---

2 (1843) 4 Moo P.C.C. 273
3 A.I.R. 1961 S.C. 1367
4 A.I.R. 1963 S.C. 1348

अपीलार्थी का समान रूप से सकारात्मक मामला यह है कि जहां तक "और कार्यवाहियों पर रोक" का संबंध है, उन्हें बाद में आवेदन और हलफनामे में जोड़ा गया है।विद्वान एकल न्यायाधीश, जिसका हम इस स्तर पर उल्लेख कर सकते हैं, ने मुख्य रूप से इस आधार पर प्रत्यर्थी के कथन पर विश्वास किया है कि यदि प्रत्यर्थी द्वारा जिला न्यायाधीश, नारनौल के समक्ष दायर स्थानांतरण आवेदन में कार्यवाही की तारीख उसे पता थी और उसमें अपीलार्थी को लिखित रूप में सूचित किया गया था, तो उसके पास उस रोक के बारे में सूचित नहीं करने का कारण हो सकता है जो 27 मई, 1998 को जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा पारित आदेश का अधिक भौतिक हिस्सा था।ऐसा प्रतीत होता है कि हमने ऊपर जो कहा है, उसके आधार पर पूरे मामले का फैसला किया गया है।

(8) प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित पहला दस्तावेज़ प्रतिवादी दिलावर सिंह के एक हलफनामे द्वारा समर्थित आवेदन है। विवाद की सराहना करने के लिए, आवेदन और शपथ पत्र को विस्तार से पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा।हम सबसे पहले आवेदन और शपथ पत्र को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं जैसा कि उन्हें टाइप किया गया था और उसके बाद उन शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें हाथ से जोड़ा गया है।आवेदन और शपथ पत्र इस प्रकार हैः—

श्री एम. एम. शर्मा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रेवाड़ी की अदालत में।

हरियाणा राज्य और अन्य

बनाम

दिलावर सिंह

विषयःकार्यवाही पर रोकः

साहब,

आवेदक निम्नानुसार प्रस्तुत करना चाहता हैः—

कि आवेदक वर्तमान अपील के इस न्यायालय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण के लिए पहले ही विद्वान जिला न्यायाधीश, नारनौल की अदालत में जा चुका है ।इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि इस अपील की कार्यवाही को स्थानांतरण आवेदन के निर्णय तक रोक दिया जाए।

स्थानःरेवाड़ी आवेदक

दिनांक 27 मई, 1998

(दिलावर सिंह)

A.F.S.O. रेवाड़ी।

हलफ़नामा

श्री एम. एम. शर्मा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रेवाड़ी के न्यायालय में

हरियाणा राज्य और अन्य

बनाम

दिलावर सिंह

हलफ़नामा

मैं, सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारी, रेवाड़ी, दिलावर सिंह, इसके द्वारा पूरी तरह से पुष्टि और घोषणा करता हुं कि

1. कि उपरोक्त शीर्षक वाली अपील इस माननीय न्यायालय में लंबित है।

2. कि आवेदक पहले ही इस न्यायालय में लंबित वर्तमान अपील को सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए विद्वान जिला न्यायाधीश, नारनौल की अदालत का रुख कर चुका है।

एस. डी./-

डिपोनेंट।

सत्यापनः

सत्यापित किया कि उपरोक्त अनुचदो के तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। 27 मई, 1998 को रेवाड़ी में सत्यापित।

दिनांक 27 मई, 1998।

डिपोनेंट

(9) आवेदन के गैर-क्रमांकित पैरा 2 और शपथ पत्र के क्रमांकित पैरा 2 की दूसरी पंक्ति में "नारनौल" शब्द के बाद जो शब्द हाथ में जोड़े गए हैं, वे इस प्रकार हैंः—

"4 जून, 1998 तक लंबित रहा और कार्यवाही रोक दी गई।"

(10) यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि "4 जून, 1998 के लिए लंबित" शब्द एक समय में लिखे गए थे जबकि "और कार्यवाही रोक दी गई" शब्द दूसरे समय में लिखे गए थे।दूसरे शब्दों में, "4 जून, 1998 के लिए लंबित" और "कार्यवाही पर रोक" एक ही समय में नहीं लिखी गई थी।यहाँ यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि "4 जून, 1998 के लिए लंबित" शब्दों के बाद, प्रत्यर्थी ने अपने आद्याक्षर डाल दिए थे और एक बार आरंभ करने के बाद, "और कार्यवाही रुक गई" शब्दों का बाद में उल्लेख किया गया था।अभिलेखों पर यह फिर से साबित होता है कि 4 जून, 1998 के लिए लंबित शब्दों के बाद उनके प्रारंभिक अक्षरों पर, प्रतिवादी द्वारा संलग्न प्रारंभिक अक्षरों पर "शब्द" और "कार्यवाहियों पर रोक" शब्दों से पहले लिखा गया है।विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः—

मेरी राय में, उन्होंने (इसमें प्रतिवादी) आवेदन दायर करने के समय "और कार्यवाही रोक दी" शब्द जोड़े।इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभिक अक्षरों पर कुछ अति-लेखन है जिसे उन्होंने "4 जून, 1998 के लिए लंबित" शब्दों के बाद रखा था, लेकिन यह आवेदन दाखिल करते समय किया जा सकता था।याचिकाकर्ता ने आगे संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया है।उन्होंने पहले सोचा कि वह स्थगन आदेश के संबंध में एक अलग पंक्ति जोड़ेंगे, लेकिन अपने आद्याक्षर डालने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और "और कार्यवाही रुक गई" शब्द जोड़ दिए।इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से बहस के समय अदालत में आवेदन की एक प्रमाणित प्रति और अपने हलफनामे की एक प्रमाणित प्रति पेश की, जिसे उसने 27 मई, 1998 को अदालत में दायर किया था।प्रमाणित प्रतियों के लिए 27 मई, 1998 को ही आवेदन किया गया था और प्राप्त किया गया था।तथ्य इस प्रकार इंगित करता है कि छेड़छाड़, यदि कोई हो, तो 27 मई, 1998 के बाद नहीं हो सकती थी।(जोर दिया गया)।

(11) हम विद्वत एकल न्यायाधीश के इन निष्कर्षो को अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों के संदर्भ में देखेंगे, लेकिन प्रतिवादी दिलावर सिंह के आवेदन और शपथ पत्र दाखिल करने के चरण पर लौटते हुए, हमारा विचार है कि हाथ में जोड़े गए शब्द ऐसे स्थान पर हैं जहां वाक्य सही नहीं है। एक उचित अर्थ बनाने के लिए "नारनौल" शब्द के बाद शब्दों को जोड़ने से वाक्य इस प्रकार पढ़ा जाएगाः—

"कि आवेदक पहले ही 4 जून, 1998 के लिए लंबित जिला न्यायाधीश, नारनौल की अदालत का रुख कर चुका है और इस अदालत में लंबित वर्तमान अपील को किसी अन्य सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।"

(12) जोड़े गए शब्दों का उचित अर्थ बनाने के लिए, आम तौर पर, इन शब्दों को पैरा के अंत में जोड़ा जाना चाहिए था, जहां प्रतिवादी को यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त जगह भी थी कि कार्यवाही "नारनौल" शब्द के बाद रोक दी गई है और फिर यह कहने के लिए कि मामले में निर्धारित अगली तारीख 4 जून, 1998 थी, न कि मामले में इसके विपरीत।हम शपथपत्र के संबंध में वही टिप्पणियां करते हैं जिन पर अतिरिक्त टिप्पणियां छोड़ते हैं जिनका उल्लेख अग्रगामी पैरास में किया जाना है, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया था।हम इस बात से सहमत हैं कि "और कार्यवाही रोक दी गई" शब्द उस समय नहीं लिखे गए थे जब "4 जून, 1998 के लिए लंबित" शब्द हाथ में इस अतिरिक्त कारण से लिखे गए थे कि "4 जून, 1998 के लिए लंबित" शब्द एक ही स्याही में होने के बावजूद, शब्दों से पतले हैं और कार्यवाही रोक दी गई थी।"4 जून, 1998 के लिए लंबित" शब्दों की तुलना में "और कार्यवाही रोक दी गई" शब्दों को देर से लिखने का एक और कारण है और वही यह है कि यदि ये सभी शब्द एक ही समय में लिखे गए होते, तो प्रतिवादी ने अंत में आरंभ किया होता और दो बार नहीं, यानी "4 जून, 1998 के लिए लंबित" शब्दों के बाद एक, दूसरा शब्दों के बाद "और कार्यवाही रोक दी गई"।हमने आवेदन और हलफनामे को मूल रूप में देखा है और आवर्धक कांच की मदद से उनकी बड़ी फोटो प्रतियां भी देखी हैं और हमारा मानना है कि "और" शब्द को प्रतिवादी के आद्याक्षरों पर अधिक लिखा गया है।दिलावर सिंह।अब विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से निपटना उचित होगा, जैसा कि ऊपर निकाला गया है।

(13) निष्कर्षों के पहले भाग में, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि मेरी राय में, उन्होंने आवेदन दायर करने के समय "और कार्यवाही रोक" शब्द जोड़े और यह कि भले ही प्रारंभिक अक्षरों पर अति-लेखन था जो उन्होंने "4 जून, 1998 के लिए लंबित" शब्दों के बाद रखा था, लेकिन यह आवेदन दायर करने के समय किया जा सकता था।(जोर दिया गया)।ऊपर निकाले गए भाग के बाद के भाग में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि दिलावर सिंह ने एक संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया था।उन्होंने पहले सोचा कि वे स्थगन आदेश के संबंध में एक अलग पंक्ति जोड़ेंगे, लेकिन अपने प्रारंभिक अक्षर डालने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और "और कार्यवाही रुक गई" शब्द जोड़ दिए और कहा कि इसमें कुछ भी अप्राकृतिक नहीं था।हम पाते हैं कि अवमानना याचिका में ऐसा मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस तरह का स्पष्टीकरण पहली बार विद्वान एकल न्यायाधीश के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ अपीलार्थी के लिखित बयान के जवाबी हलफनामे में आया है, हमारा विचार है कि निष्कर्षों में कुछ विरोधाभास हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।या तो प्रत्यर्थी दिलावर सिंह ने आवेदन और हाथ में हलफनामे में उल्लिखित सभी शब्दों को एक ही समय में लिखा था या उन्होंने दो अलग-अलग अवसरों पर "4 जून, 1998 के लिए लंबित" और "और कार्यवाही रोक दी गई" शब्दों का उल्लेख किया था। अगर उन्होंने ये सभी शब्द एक बार में लिखे थे, तो उनके लिए "4 जून, 1998 के लिए लंबित" शब्दों के बाद अपने

प्रारंभिक अक्षरों पर ओवर-राइटिंग को समझाने का कोई सवाल ही नहीं था।यह मानते हुए कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, का अर्थ यह हो सकता है कि "4 जून, 1998 के लिए लंबित" शब्दों और कार्यवाहियों का उल्लेख किए जाने के तुरंत बाद, निष्कर्ष संभावनाओं के क्षेत्र में आते हैं, न कि एक निश्चित निष्कर्ष के रूप में।हम केवल यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि यदि दिलावर सिंह के लिए "4 जून, 1998 के लिए लंबित" शब्द लिखने के तुरंत बाद "शब्दों का उल्लेख करना और कार्यवाही पर रोक लगाना" संभव था, तो यह भी संभावना हो सकती है कि "और कार्यवाही पर रोक" शब्द बाद में जोड़े गए थे, जैसा कि अपीलार्थी के मामले में था।मामला यहाँ नहीं टिका है क्योंकि हम मामले के अभिलेखों से आने वाले आंतरिक साक्ष्य पाते हैं जो हमारे विचार को मजबूत करेंगे कि "और कार्यवाही रुकी" शब्दों को बाद में जोड़ा गया था।इस स्तर पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलार्थी के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मामले में उसका कोई व्यक्तिगत हित था।यह प्रतिवादी दिलावर सिंह का मामला भी नहीं है कि राज्य ने अपीलार्थी को प्रभावित किया था और न ही यह उसका मामला है कि अधिकारी ने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है या वह अप्राकृतिक उत्साह का अधिकारी है।दुर्भावनापूर्ण या यह कि अधिकारी अन्यथा अशिष्ट होने का कोई आरोप नहीं है, प्रतिवादी द्वारा किए जाने के अलावा, हम, प्रचुर सावधानी के मामले में, इस अधिकारी के गोपनीय रिकॉर्ड के लिए भेजे गए हैं।18 वर्षों की अवधि में अपने न्यायिक कार्यकाल के दौरान, इस न्यायालय के निरीक्षण न्यायाधीशों द्वारा अपीलार्थी को एक ईमानदार व्यक्ति बताया गया है।उन्हें एक भी प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं मिली है।

(14) हम इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं कि उनके गोपनीय रिकॉर्ड का चित्रण न तो बहुत आवश्यक है और न ही प्रासंगिक है, सिवाय एक सीमित उद्देश्य के, यह देखने के लिए कि क्या अधिकारी के पास पीसने के लिए कोई कुल्हाड़ी हो सकती है या वह अशिष्ट था या उसके स्वभाव में अंतर्निहित जिद्दीपन था जो हो सकता था की आगे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का जानबूझकर पालन न करना दिखाएँ।

(15) हम उन अतिरिक्त कारकों के बारे में जानते हैं जो इस दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आइए हम अपीलार्थी द्वारा 27 मई, 1998 को राज्य को स्थगन देने वाले आदेश की जांच करें। वही इस प्रकार हैः—

उपस्थित : श्री दलीप सिंह, अपीलार्थी के जी पी ।

श्री दिलावर सिंह, व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी।

इस अपील का नोटिस अधिवक्ता श्री एन. सी. सचदेवा को जारी किया गया था।वह कुछ समय पहले मेरे पास आए और मुझसे कहा कि वह प्रतिवादी की ओर से इस मामले में पेश नहीं हो रहे हैं।सुना ।विद्वान सरकारी प्लीडर

द्वारा राज्य के लिए यह प्रार्थना की गई थी कि इस अपील के अंतिम निर्णय तक निचली अदालत के विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगाई जाए।श्री दिलावर सिंह प्रत्यर्थी द्वारा मेरे समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस अपील की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए क्योंकि उनके द्वारा विद्वान जिला न्यायाधीश, नारनौल के समक्ष स्थानांतरण आवेदन दायर किया गया है और इसे 4 जून, 1998 के लिए निर्धारित किया गया है।इस आवेदन के समर्थन में मेरे समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया है।विद्वान जिला न्यायाधीश, नारनौल का यह दिखाने का कोई आदेश नहीं कि इस मामले की कार्यवाही पर विद्वान जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा रोक लगा दी गई है, मेरे सामने पेश किया गया है।मैंने निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश को पढ़ा है।निचली अदालत के 16 मई, 1998 के आदेश के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।6 जून, 1998 को विद्वत जिला न्यायाधीश, नारनौल के अध्यक्ष की प्रतीक्षा के लिए, यदि कोई हो।निर्धारित तिथि के लिए एल. सी. आर. की भी मांग की जाए।

एसडी/-

एडीजे रेवाड़ी। 27मई, 1998 "

(16) आदेश को फिर से पढ़ना पर दर्शित है की अपीलार्थी ने उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उनके समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि इस अपील की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए क्योंकि स्थानांतरण आवेदन दिलावर सिंह द्वारा विद्वान जिला न्यायाधीश, नारनौल के समक्ष दायर किया गया था और इसे 4 जून, 1998 के लिए निर्धारित किया गया था।उन्होंने आगे उल्लेख किया कि उनके समक्ष आवेदन के समर्थन में एक हलफनामा भी दायर किया गया था।यह आदेश आगे उल्लेख किया गया है कि विद्वान जिला न्यायाधीश, नारनौल का यह दिखाने के लिए कोई आदेश नहीं है कि इस मामले की कार्यवाही पर विद्वान जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा रोक लगा दी गई है, उनके सामने पेश किया गया है।यह पक्षकारों के विद्वान वकील के बीच स्वीकार किया जाता है और इसलिए आदेश से ही यह भी स्पष्ट है कि जब उपरोक्त आदेश पारित किया गया था, तब दिलावर सिंह व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे।प्रतिवादी दिलावर सिंह के लिए इस बात का कोई सवाल ही नहीं था कि उन्होंने जोरदार आवाज में विरोध नहीं किया कि उन्होंने अपने आवेदन और हलफनामे में उल्लेख किया था कि जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, अगर वास्तव में और वास्तविकता में उन्होंने अपने आवेदन और हलफनामे में ऐसा उल्लेख किया था।अपीलार्थी की अदालत से अपील को स्थानांतरित करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, 4 जून, 1998 को जिला न्यायाधीश, नारनौल के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

विद्वान जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा पारित आदेश, अपीलार्थी की अदालत से उक्त अपील को स्थानांतरित करते हुए, निम्नानुसार हैः—

"उपस्थित : श्री आर. पी. सैनी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री पी. डी. गुप्ता, राज्य के जी. पी.

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि श्री एम. एम. शर्मा, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, प्रथम रेवाड़ी, इस मामले में 9 फरवरी, 1998 को पक्षों के बीच अपील पर निर्णय लेते समय पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं।आवेदक के विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि आवेदक द्वारा दायर कैविएट आवेदन के बावजूद, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री एम. एम. शर्मा ने विरोधी पक्ष को स्थगन आदेश दे दिया है।

2. आवेदक की ओर से दी गई दलीलों के इस अंतिम पहलू पर कोई टिप्पणी किए बिना और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री एम. एम. शर्मा, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, प्रथम रेवाड़ी, पहले ही इस अपील में शामिल मामले के संबंध में अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं, इस अपील को उनकी अदालत से वापस ले लिया जाता है और कानून के अनुसार निपटारे के लिए श्री आर. के. बिश्नोई, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इलंद रेवाड़ी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाता है।पक्षकार 6 जून, 1998 को अंतरिती अदालत में पेश होंगे।कागजात भेजे जाएँ।

(17) जबकि स्थानांतरण आवेदन पर विचार करते हुए, जिला न्यायाधीश ने कहा कि दिलावर सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि कैविएट आवेदन दायर किए जाने के बावजूद, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने स्थगन आदेश दिया था। विरोधी पक्ष के लिए।दिलावर सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील का यह तर्क नहीं था कि जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा दी गई रोक के बावजूद, शर्मा ने विरोधी पक्ष को रोक लगा दी थी।दिलावर सिंह के वकील ने केवल इस बात का उल्लेख किया कि केवल चेतावनी दायर की गई है।

(18) दिलावर सिंह द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण आवेदन के संबंध में उनके आवेदन के समर्थन में दिए गए जवाब देने वाले हलफनामे को 4 जून, 1998 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और अपीलार्थी के समक्ष मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है, यह देखा जा सकता है कि भले ही हाथ में दिए गए हलफनामे में किए गए परिवर्धन दिलावर सिंह द्वारा शुरू किए गए थे, लेकिन वे उस व्यक्ति द्वारा शुरू नहीं किए गए थे जिसके सामने शपथ पत्र लिया गया था।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड 4 का अध्याय 12 भाग बी शपथ पत्रों से संबंधित है।इसके नियम 9 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः—

(9) शपथपत्रों की अंतर्वस्तु (i) तथ्यों के किसी भी विवरण वाले प्रत्येक शपथ पत्र को पैराग्राफ में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक पैराग्राफ को लगातार गिना जाएगा, और, जितना हो सके उतना, विषय के एक अलग हिस्से तक सीमित होगा।"

(19) नियम 10 जिसका वर्तमान मामले के तथ्यों से सीधा संबंध है, इस प्रकार हैः—

"10. शपथ पत्र आम तौर पर उन तथ्यों तक सीमित होते हैं जो प्रतिवादी की जानकारी में होते हैं।—

(i) XXXXXXXX

(ii) शपथ-पत्र में सभी अंतर्वेशन, परिवर्तन या विलोपन की शुरुआत शपथ लेने वाले व्यक्ति और उस व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसके सामने यह शपथ ली जाती है।इस तरह की अंतःरेखाएँ, परिवर्तन और विलोपन इस तरह से किए जाएंगे कि मूल विषय के साथ इसे पढ़ना असंभव या कठिन न हो।यदि इस तरह के मामले को मिटा दिया गया है ताकि इसे पढ़ना असंभव या कठिन हो जाए, तो इसे मार्जिन पर फिर से लिखा जाएगा और उस व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाएगा जिसके सामने शपथ पत्र लिया गया है।"

(20) ऊपर दिए गए नियम 10 का उप-नियम (ii) यह स्पष्ट करता है कि सभी अंतःरेखाएं, परिवर्तन या विलोपन न केवल शपथ पत्र की शपथ लेने वाले व्यक्ति द्वारा शुरू किए जाने हैं, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा जिसके सामने यह शपथ ली गई थी।स्वीकार करते हुए, शपथ आयुक्त, जिनके समक्ष शपथ पत्र शपथ ली गई थी, ने शपथ पत्र में हाथ में किए गए परिवर्धन की शुरुआत नहीं की थी।यह अदालत के विचार को और मजबूत करता है कि जब उसके समर्थन में आवेदन और हलफनामा अदालत में दायर किया गया था, तो इसमें "और कार्यवाही पर रोक" शब्द शामिल नहीं थे।

(21) जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, अभिलेखों पर उपलब्ध प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न पर अपने विचार को व्यक्त करने के बाद, एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों पर कि यदि दिलावर सिंह को जिला न्यायाधीश, नारनौल के समक्ष लंबित अपने स्थानांतरण आवेदन में तारीख के तथ्य के बारे में पता था और विधिवत सूचित किया गया था, तो उनके लिए अपीलार्थी को उसमें रोक लगाने के बारे में न तो जानने या सूचित करने का कोई अवसर नहीं था, जिस पर अभी भी टिप्पणी की जानी बाकी है।यह दोहराया जा सकता है कि यह इस धारणा पर है कि दिलावर सिंह को उनके द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण आवेदन में तारीख के बारे में पता था और इसलिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, कि मामला अपीलार्थी के खिलाफ हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ दोषसिद्धि और सजा दर्ज की गई है।हम विद्वान एकल न्यायाधीश के प्रति पूरी विनम्रता और सम्मान के साथ यह उल्लेख करना चाहेंगे कि न्यायालय की अवमानना के आरोप के मूल का

गठन करने वाले तथ्य को साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए न कि मान्यताओं पर।यह मुख्य सिद्धांत है जिसे विश्वास के निष्कर्ष को दर्ज करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।हम इस बात की सराहना करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जो कुछ भी देखा गया है वह प्रासंगिक है, लेकिन जिस प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है वह यह है कि क्या वह उचित है और अवमानना के कानून के न्यायशास्त्र के सिद्धांतों को संतुष्ट करता है।हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बनाई गई धारणा कि चूंकि दिलावर सिंह अपीलार्थी को उनके द्वारा पसंद किए गए स्थानांतरण आवेदन में रोक लगाने के बारे में जानते थे और सूचित करते थे, दोषसिद्धि के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऊपर उल्लिखित धारणा पर एक निश्चित निष्कर्ष संभवतः नहीं निकाला जा सका।धारणाएँ या अनुमान तथ्यों की कटौती और मानव मन की कल्पना की उड़ान हैं।कल्पना की उड़ान दोषपूर्ण हो सकती है, धारणा या अनुमान आकर्षक या वास्तविकता से व्यापक रूप से दूर हो सकते हैं।हम यहाँ यह भी जोड़ सकते हैं कि यदि इस प्रकार की धारणा करना संभव था, जैसा कि किया गया है, तो अपीलार्थी के पक्ष में एक धारणा भी की जा सकती है कि उसे दिलावर सिंह द्वारा दी गई रोक के बारे में इस कारण से सूचित नहीं किया गया था कि उसके लिए कोई कारण या अवसर नहीं था ताकि कार्यवाही पर रोक न लगाई जा सके यदि उसे वास्तव में सूचित किया गया था, विशेष रूप से जब उसने अपने आदेश में इस प्रभाव से प्राप्त जानकारी का उल्लेख किया था कि स्थानांतरण आवेदन दायर किया गया था जिसमें अगली तारीख 4 जून, 1998 थी।

(22) वहाँ एक अतिरिक्त कारण है कि क्यों फिर जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस मामले में निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए।जहाँ तक अवमानना याचिका का संबंध है, उसमें कुछ भी सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया है कि दिलावर सिंह को उसी दिन जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा स्थगन दिए जाने के बारे में कैसे पता चला जब अपीलार्थी द्वारा स्थगन दिया गया था, हालांकि, यह एक स्वीकृत मामला है कि रेवाड़ी लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है।नारनौल से।हालाँकि, जब अपीलकर्ता ने अपने लिखित बयान में रोक के बारे में मौखिक या लिखित रूप से सूचित किए जाने से इनकार किया और दिलावर सिंह के उक्त बयान को गंभीरता से चुनौती देते हुए कहा कि प्रतिवादी ने अपने हाथ में आवेदन और हलफनामे को हस्तक्षेप किया था, इन शब्दों का उल्लेख करते हुए "और कार्यवाही रुक गई", अहमद के साथ मिलीभगत में, दिलावर सिंह ने कई दस्तावेजों और अन्य व्यक्तियों के हलफनामों के साथ एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया।रेवाड़ी में वकालत करने वाले वकील गोकल चंद यादव के हलफनामे में, दिलावर सिंह के अतिरिक्त हलफनामे के साथ संलग्न किया गया है कि यह उल्लेख किया गया था कि 27 मई, 1998 को सुबह लगभग 1 बजे उन्होंने नारनौल से फोन पर एक दलीप सिंह को सूचित किया था कि स्थानांतरण आवेदन में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है और दलीप सिंह से यह भी कहा गया है कि वह दिलावर

सिंह को वह जानकारी दें जो उन्होंने उन्हें टेलीफोन पर दी थी।जहां तक दलीप सिंह का संबंध है, उन्होंने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपना हलफनामा दायर नहीं किया कि उन्हें अधिवक्ता गोकल चंद यादव से ऐसी जानकारी मिली थी, जो भले ही रेवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उस विशेष दिन और समय पर नारनौल में थे। दलीप सिंह का हलफनामा इस अपील के लंबित रहने के दौरान ही दायर किया गया था और वह भी जब अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री चीमा ने अपनी दलीलें पूरी की थीं और मामला स्थगित कर दिया गया था।हमारा मानना है कि दलीप सिंह एक महत्वपूर्ण गवाह थे और उनका हलफनामा पहले ही दाखिल किया जाना चाहिए था।दलीप सिंह का शपथ पत्र दाखिल करना, इस अपील के लंबित रहने के दौरान और वह भी अपीलार्थी के वकील द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद, हमें एक विचार के बाद प्रतीत होता है।अधिक दिलचस्प बात यह है कि जिला न्यायाधीश, नारनौल के समक्ष प्रत्यर्थी दिलावर सिंह द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण आवेदन में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला वकील अधिवक्ता गोकल चंद यादव नहीं था।श्री आर. पी. सैनी, अधिवक्ता ने जिला न्यायाधीश, नारनौल की अदालत में उनका प्रतिनिधित्व किया था, जैसा कि नारनौल के जिला न्यायाधीश श्री प्रीतम पाल द्वारा 27 मई, 1998 को पारित आदेश, अनुलग्नक पी-1 से स्पष्ट होगा।उनकी उपस्थिति में स्थानांतरण आवेदन को 4 जून, 1998 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और इस बीच अपीलार्थी के समक्ष लंबित अपील में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। गोकल चंद के हलफनामे में एक भी शब्द का उल्लेख नहीं है। यादव, अधिवक्ता, अनुलग्नक पी-10 ने कहा कि श्री आर. पी. सैनी, अधिवक्ता ने उन्हें दलीप सिंह या प्रतिवादी दिलावर सिंह में से किसी एक को सूचित करने के लिए कहा था कि रोक लगा दी गई है।हलफनामा, अनुलग्नक पी-10 से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है कि क्यों और किस संबंध में गोकल चंद यादव जिला न्यायाधीश, नारनौल की अदालत में मौजूद थे, जब दिलावर सिंह द्वारा दिए गए स्थानांतरण आवेदन में रोक लगा दी गई थी।केवल इतना उल्लेख किया गया है कि इस मामले को जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा सुबह 9:30 बजे उठाया गया था और अपील में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।यह दिलावर सिंह का मामला नहीं है कि उन्होंने अधिवक्ता श्री गोकल चंद यादव से स्थानांतरण आवेदन में पारित आदेश से उन्हें अवगत कराने का अनुरोध किया था।श्री यादव के शपथ पत्र में भी ऐसा नहीं है।इसके अलावा, मामले के अभिलेखों से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है जिससे यह पता चले कि गोकल चंद यादव को इस तथ्य के बारे में पता था कि दिलावर सिंह 27 मई, 1998 को रेवाड़ी की अदालतों में उपस्थित होंगे।इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 27 मई, 1998 को अपीलार्थी के समक्ष सुनवाई के लिए आई अपील में भी गोकल चंद यादव दिलावर सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नहीं थे।निचली अदालत में उनके वकील श्री सचदेवा थे और चूंकि कैविएट दायर किया गया था, इसलिए यह माना जाता है कि स्थगन मामले को सुनवाई के लिए लेने से पहले उन्हें नोटिस जारी किया गया था।तथ्यों से, जैसा कि ऊपर पूरी तरह से विस्तृत किया गया है, यह संभव है कि

दिलावर सिंह को केवल विद्वान जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा निर्धारित तिथि के बारे में पता चला हो और आगे की कार्यवाही पर भी रोक नहीं लगाई गई हो।इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दिलावर सिंह को जो पहली जानकारी मिली होगी, वह केवल तारीख तय करने के संबंध में थी।

(23) प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करते हुए लर्न लर्नेड काउंसल, वो का तर्क है कि प्रत्यर्थी के लिए आवेदन करने और 27 मई, 1998 को ही आवेदन और हलफनामे की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं था, जिसमें सभी शब्दों यानी "4 जून, 1998 के लिए लंबित" और "और कार्यवाही रुक गई" का उल्लेख किया गया था क्योंकि दिलावर सिंह के लिए न तो कोई समय था और न ही कोई अवसर था कि उन्होंने "शब्दों का अंतर्वेशन किया और" बाद में कार्यवाही रोक दी गई, जैसा कि अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का तर्क है।यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी इस मामले को ध्यान में रखा है और कहा है कि "इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से बहस के समय अदालत में आवेदन की एक प्रमाणित प्रति और अपने हलफनामे की एक प्रमाणित प्रति पेश की, जिसे उन्होंने 27 मई, 1998 को अदालत में दायर किया था।प्रमाणित प्रतियों के लिए 27 मई, 1998 को ही आवेदन किया गया था और प्राप्त किया गया था।तथ्य इस प्रकार इंगित करता है कि छेड़छाड़, यदि कोई हो, तो 27 मई, 1998 के बाद नहीं हो सकती थी।जबकि, हम विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं कि छेड़छाड़ 27 मई, 1998 के बाद नहीं हो सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत में आवेदन और हलफनामा दायर किए जाने के बाद राशि नहीं हो सकती थी।यह बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा एक आदेश पारित करने और मामले को स्थगित करने के बाद, फाइल अहलमाद के पास जाती है।यदि कार्यवाही या आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया जाता है, तो फाइल प्रतिलिपि शाखा में भी जाती है।दिलावर सिंह द्वारा आवेदन और हलफनामे की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने से पहले, फाइल कई हाथों में जानी चाहिए थी।आवेदन और शपथ पत्र के साथ छेड़छाड़ करने और 27 मई, 1998 को ही "और कार्यवाही पर रोक" शब्द डालने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा मामले को स्थगित करने के बाद, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।तब प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि दिलावर सिंह के लिए उच्च न्यायालय के निरीक्षण न्यायाधीश को शिकायत करने का कोई सवाल ही नहीं था कि अपीलकर्ता, जिला न्यायाधीश, नारनौल द्वारा दी गई रोक के बावजूद, मामले को आगे बढ़ा था, अगर दिलावर सिंह को रोक दिए जाने के बारे में पता नहीं था और उन्होंने अपने आवेदन और हलफनामे में इस तरह के तथ्य का उल्लेख नहीं किया था।विद्वान वकील के इस तर्क में भी हमें कोई योग्यता नहीं मिलती है।जैसा कि हम पहले ही ऊपर मान चुके हैं, अगर दिलावर सिंह को पहली बार में जिला न्यायाधीश, नारनौल के समक्ष अपने स्थानांतरण आवेदन में तय की गई अगली तारीख के बारे में पता चला था, न कि स्थगन की मंजूरी के बारे में, और

रोक के बारे में बाद में पता चला था, जाहिर है जब उन्होंने निरीक्षण न्यायाधीश से शिकायत की थी, तब तक उन्हें रोक की जानकारी मिल गई थी।इस प्रकार, दिलावर सिंह द्वारा उच्च न्यायालय के निरीक्षण न्यायाधीश को की गई शिकायत पर कुछ भी निर्भर नहीं करता है।

(24) ऊपर की गई चर्चा से, हम इस राय पर पोहोचे हैं कि अपीलार्थी को उच्च न्यायालय, यानी जिला न्यायाधीश, नारनौल की अदालत द्वारा दी गई रोक के बारे में जानकारी नहीं थी और प्रत्यर्थी द्वारा बाद में "और कार्यवाहियों पर रोक" शब्द जोड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी जब अपीलार्थी पहले ही अंतरिम आदेश पारित कर चुका था।परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है, हमारी राय है कि अपीलार्थी को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी नहीं थी और उसने जानबूझकर उसकी अवज्ञा नहीं की थी।किसी भी मामले में, यह बहुत संदिग्ध है कि उन्हें ऐसा ज्ञान था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को किसी विशेष मामले की सुनवाई करने में रुचि नहीं होनी चाहिए, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी कहा है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को किसी भी मामले की सुनवाई और निर्णय लेने से डरना नहीं चाहिए।

(25) यह सुस्थापित है कि "संदेह" को "प्रमाण" के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।भले ही यह संदेहपूर्ण हो कि अपीलार्थी को स्थानांतरण आवेदन में कार्यवाही पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी नहीं थी, हमारे विचार में अपीलार्थी को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अदालत की अवमानना करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।अतः यह अपील स्वीकार किए जाने के योग्य है और तदनुसार स्वीकार की जाती है।ऐसा करते समय, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर देते हैं।

(26) इस आदेश के साथ भाग लेने से पहले, हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि यदि, राज्य ने प्रतिवादी दिलावर सिंह के निलंबन पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ दायर अपील में, रोक के लिए नहीं कहा था, तो अपीलकर्ता ने इस जानकारी पर भी कि जिला न्यायाधीश, नारनौल की अदालत में स्थानांतरण आवेदन दायर किया गया था और अगली तारीख 4 जून, 1998 निर्धारित की गई थी, सामान्य रूप से मामले को स्थगित कर देना चाहिए था।हम निश्चित रूप से मामले के साथ अपनी कार्यवाही के अपीलार्थी के आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणी करते, भले ही उसे केवल स्थानांतरण आवेदन दाखिल करने और सुनवाई की अगली तारीख के बारे में सूचित किया गया था।यदि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्य ने ठहराव के लिए दबाव नहीं डाला होगा।हम अपीलार्थी द्वारा स्थगन देने या अस्वीकार करने के संबंध में विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह उक्त मामले में किसी भी पक्ष के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल होगा।हम केवल पारित करते हुए देखते हैं और वह भी

वर्तमान मामले पर निर्णय लेने के उद्देश्य से केवल यह कि अधीनस्थ अदालत ने दिलावर सिंह के निलंबन पर उनके खिलाफ जांच लंबित रहने तक रोक लगा दी थी और हो सकता है कि अपीलार्थी ने अपील के गुण-दोष और उसमें शामिल तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण आवेदन में निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए मामले को स्थगित नहीं किया हो।इन परिस्थितियों में, हम राज्य द्वारा दायर अपील में आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगाने में अपीलार्थी के आचरण पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उसे सूचित किया गया था कि एक स्थानांतरण आवेदन पहले ही दायर किया जा चुका है और मामला 4 जून, 1998 के लिए निर्धारित किया गया है।

(27) हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि प्रतिवादी दिलावर सिंह ने कुछ दस्तावेजों के साथ इस अपील में जवाब दाखिल किया है।हालाँकि, उक्त दस्तावेजों के बारे में कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किए गए थे, लेकिन हमने उक्त उत्तर और दस्तावेजों के आधार पर तर्क सुने हैं, लेकिन वे भी अपीलार्थी के मामले को मजबूत नहीं करते हैं।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा